>

Title: Need for four-laning of National Highway No. 12 on Jabalpur-Bhopal stretch.

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): माननीय सभापति महोदया, किसी भी देश में उसके विकास के लिए सड़कें उसकी रीढ़ और प्रमुख आधार होती हैं, लेकिन अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में एक ओर जहाँ ऊँची विकास दर के आँकड़ों के साथ यह बताने का प्रयास होता है कि हमने कितना विकास किया है, वहीं दूसरी ओर सड़कों की दुर्दशा वास्तविक स्थिति को उजागर करने के साथ-साथ हमारे विकास की गति को भी रोक रही है।

महोदया, मध्य प्रदेश जो हमारे देश के मध्य में स्थित है, यहाँ से 10 राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुज़रते हैं। इन राजमार्गों की हालत आज अत्यंत चिन्ताजनक है। इनके रखरखाव और उन्नयन की ज़िम्मेदारी एऩएचएआई के पास है। हालत यह है कि कुल मिलाकर 3827 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों में से 2393 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बहुत खराब स्थिति में हैं। मध्य प्रदेश में अपने गंतव्य तक जाने के लिए यदि किसी के पास नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों विकल्प मौजूद हों, तो वह बेहतर विकल्प के रूप में स्टेट हाईवे को चुनता है क्योंकि अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी मध्य प्रदेश ने अपनी सभी सड़कों को बहुत अच्छा बना लिया है। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि या तो मध्य प्रदेश से होकर गुज़रने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को तत्काल ठीक किया जाए अथवा केन्द्र सरकार इन्हें डीनोटिफाई कर दे ताकि मध्य प्रदेश की सरकार स्वयं इनका निर्माण कर सके।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहूँगा। मेरा संसदीय क्षेत्र जबलपुर जो महाकौशल के साथ-साथ पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश का मुख्यालय है, यहाँ से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुज़रते हैं - एन.एच. 7, एन.एच.12 और एन.एच.12ए, और तीनों ही दुर्दशा का शिकार हैं। एन.एच.7 में कटनी से जबलपुर, एन.एच.12ए में जबलपुर से मंडला-चिल्पी तथा एन.एच.12 में जबलपुर से भोपाल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जबलपुर-भोपाल राजमार्ग अर्से से अपने उन्नयन की प्रतीक्षा कर रहा है। पिछले दिनों इस राजमार्ग को टू लेन से फोर लेन में बदलने का निर्णय केन्द्र सरकार के द्वारा लिया गया था। 289 किलोमीटर की यह सड़क जबलपुर से शहपुरा-बिलखेड़ा होकर भोपाल जाती है जो बीओटी मोड से निर्मित होना है। इसके लिए रिक्वैस्ट और प्रपोज़ल सबमिट किये जा चुके हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एप्रेज़ल कमेटी द्वारा क्लियरैन्स भी दिया जा चुका है। इसके लिए मातृ कैबिनेट कमेटी ऑन इनफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा मंज़ूरी मिलना शेष है।

महोदया, आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव बंद करते हुए तत्काल कैबिनेट कमेटी इस प्रोजैक्ट को स्वीकृति प्रदान करे तथा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की उखड़ी हुई सड़कों को ठीक करे अथवा उन्हें डीनोटिफाइ करे ताकि मध्य प्रदेश सरकार स्वयं इनका रखरखाव एवं उन्नयन कर सके।

सभापति महोदया : श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र एवं श्री वीरेन्द्र कुमार का नाम श्री राकेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किया जाता है।